



२०१७ से पहले उत्तर प्रदेश माफिया राज और अराजकता से था ग्रस्त-योगी आदित्यनाथ

भदोही (उप्र) ०४/१०
(संवाददाता): उज्जर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
रविवार को कहा कि वर्ष 2017
में उनके सप्ता में आने से पहले
गन्ध अराजकता और माफिया
राज के लिए बदनमा था तथा
नीतिगत जड़ता के कारण यहां
के कारीगरों के हाथ बंधे हुए
थे। भदोही में 'कारपेट एक्सपोजे
मार्ट' में आयोजित अंतरराष्ट्रीय
कालीन मेले के स्वर्ण जयंती
संस्करण को संबोधित करते
हुए आदित्यनाथ ने कहा कि
तब तक राज्य 'बीमारू'
अर्थव्यवस्था में बदल चुका था,
ज्योंकि 'बीमारू मानसिकता'
वाली सरकारों के कारण यहां
सुरक्षा, बुनियादी ढांचे,
प्रौद्योगिकी और बाजार की
सुविधाओं का अभाव था।
मुख्यमंत्री ने कहा, " वर्ष
2017 से पहले अराजकता,
माफिया राज, गुंडागर्दी, कर्फ्यू
और दंगे होते थे। नीतिगत

जड़ता थी, बाजार की सुविधाएँ नहीं थीं, प्रौद्योगिकी नहीं थी और सरकार का कोई सहयोग नहीं था। कारीगरों को बिजली और सड़क तक की सुविधा नहीं मिलती थी तथा सुरक्षा की स्थिति भी ठीक नहीं थी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति के कारण बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े कामगारों को आजीविका की तलाश में पलायन करना पड़ा, जबकि जो लोग यहीं रह गए उन्हें सुरक्षित माहौल के अभाव में कठिनाई का का सामना करना पड़ा। उच्च प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्ववर्ती विपक्षी दलों की सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीच के कालखंड को मानसिकता की 'बीमारी' में प्रसिकता की सरकारों ने इस राज्य को बीमारी बना दिया था। आदित्यनाथ ने कहा, "मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अपनी-

अपनी प्रदर्शनी के साथ 2277 से अधिक लोगों के अलावा 65 देशों के 450 से अधिक विदेशी खरीदार, इस अन-उत्तराष्ट्रीय प्रदर्शनी का हिस्सा बने हैं। इनमें से 106 खरीदार 'ब्रिज' देशों से संबंधित हैं।' उ-होंने राज-य के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हुए कहा, 'हमारे उ-प्र के पास ज्या नहीं था, उ-प्र असोमित उत्पादन का प्रदेश था, लेकिन बीच के कालखंड में प्रदेश की 'बीमारू' मानसिकता वाली सरकारों ने इस उ-प्र को 'बीमारू' बना दिया।' प्रधानमंत्री नरे-न्द्र मोदी के नेतृत्व और 'डबल इंजन' सरकार के कार्य का ज्योति देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि जो उ-प्र कभी 'बीमारू' था, आज वह अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बन गया है और भारत के उ-प्र राज्य आधि-य वाले राज्य के रूप में अपने कार्यक्रम

को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई समाज और कोई क्षेत्र हाताश और निराश होकर अपनी 'बीमारी' मानसिकता के सस्य कार्य करता है तो परिवार भी उसी प्रकार देखने को मिलते हैं। एक लंबे समय तक हमें उस पहचान का मोहताज बनना पड़ा।" योगी ने उध को "बीमारी" राज्य की श्रेणी से मुक्त करने का दावा करते हुए कहा कि पहले हमारा जो कारीगर था, वह श्रमिक के रूप

मैं अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर था, हमारा जो अन्नदाता था, वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था, लेकिन आज यह देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता प्रदेश है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान उग्र के नौजवान पलायन के लिए मजबूर थे। आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले यहाँ 'बीमारू' मानसिकता उग्र को ग्रसित कर चुकी थी। आदित्यनाथ ने कहा कि 2017

के पहले उग्र का खजाना खाली था, लेकिन उनकी सरकार ने 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) की योजना प्रारंभ की और भदोही के लिए कालीन को उसका हिस्सा बनाया।

मुज्यमंत्री ने कहा कि एक-एक धागे के साथ कारीगर की कल्पना, उसका परिश्रम और माटी का गौरव जुड़ा होना है। उन-होंने कहा कि जिन हाथों ने सदियों से कालीन बुना है, उन्हीं हाथों में आज नई तकनीक और नई डिजाइन होनी चाहिए और उसके पास नया बाजार भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए बाजार से जोड़ने के लिए सरकार सुविधा उपलब्ध करा रही है। आदित्यनाथ ने कहा कि आज उज्जर प्रदेश में न तो दंगे होते हैं और न ही कर्फ्यू लगता है। उन्होंने कहा, अब कोई माफिया पिस्तौल लहराकर लोगों के खुले आम धमकी नहीं दे

सकता... आज आपके पास तकनीक, डिजाइन, बाजार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा है।" मुज्यमंत्री ने कहा कि राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, जबकि 7.5 लाख करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाओं के जल्द शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में अब उप्र की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है और यहाँ सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। खबरें पढ़ें

उन्होंने कहा कि संत रविदास नगर-मिर्जापुर-वाराणसी सिल्क और कालीन जलस्टर ने लगभग 6,100 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और 2017 के बाद से राज्य की अर्थव्यवस्था तीन गुना से ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि उग्र में देश का सबसे बड़ा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) है, जिसमें लगभग 96 लाख इकाई हैं, और सरकार हर इकाई को पांच लाख रुपये का बीमा कवर देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में करीब 14 हजार कारखाने थे, जिनकी संख्या अब 35 हजार से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के 55 प्रतिशत मोबाइल फोन और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का निर्माण उद्यम प्रदेश में हो रहा है, जबकि देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग गलियारे के छह नोड पर काम चल रहा है और प्रदेश में 12 निजी औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। निवेश मित्र, निवेश साझेदार और उद्यम मित्र जैसी व्यवस्थाओं के जरिये निवेशकों को हरसंभव सुविधाएं दी जा रही हैं।

पाकिस्तान को सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने के आरोप में असम से दो गिरफ्तार

गुवाहाटी ०४/१०
(संवाददाता): असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि सुरक्षा संबंधी जानकारी पाकिस्तान को पहुँचा कराने के आरोप में सेना के एक सेवानिवृत्त जवान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने कहा कि सेना के सेवानिवृत्त जवान को अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर की गई। शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में जासूसी के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर कहा, “आज केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर असम पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सेना का सेवानिवृत्त जवान है जो फिलहाल सेना में अनुबंध के

आधार पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा, “आरोप है कि वे पाकिस्तान के संपर्क में थे और सैना की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम उन्हें केंद्रीय एजेंसियों को सौंप देंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों को कथित तौर पर उन लोगों ने ‘मोहपाश’ में फंसाया था, जो उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे।

इससे पहले रविवार को असम पुलिस ने एक बयान में कहा था कि विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने यहां किराये में मकान में रह रहे बिहार निवासी को एक व्यक्ति को कथित जासूसी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। बयान के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सुरक्षा बलों से संबंधित गोपनीय जानकारी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े व्यक्ति को कथित तौर पर सौंपा करारने

समेत ऐसी गतिविधियों में उसकी सलिलता सामने आई है। आरोपी की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी अभिषेक कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध के बारे में शुरुआती सूचना तेजपुर स्थित गजराज स्कूल की सैन्य खुफिया इकाई ने साझा की थी। पुलिस के अनुसार, एसटीएफ ने सोनितपुर पुलिस के साथ समन्वय करके सिंह के बारे में और जानकारी जुटाई। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े व्यक्ति के निर्देश पर राक्षवरीधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था। पुलिस ने कहा, "इस सूचना के आधार पर तीन और चार अक्टूबर की दरज्यानी रात असम एसटीएफ ने अभियान चलाया और गुवाहाटी स्थित कारागार के माफक से 31 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।"

नयी दिल्ली ०४/१० (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि 2026 के एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश को अपने दिल के हर सदस्य पर गर्व है, जिन्होंने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हमारे सभी पदक विजेताओं, विशेष रूप से शानदार प्रदर्शन करने वाली हमारी महिला खिलाड़ियों को बधाई। राष्ट्रपति ने कहा, हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, कौशल और दृढ़ता ने देश को बहुत सम्मान दिलाया है। आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत 85 पदकों (21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य) के साथ सबसे अधिक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। यह चीन के हांगझोउ में हुए पिछले संस्करण



की तुलना में 21 पदक कम है। आइची-नागोया एशियाई खेल 19 सितंबर को शुरू हुए थे। समापन रविवार को जापान के नागोया में हुआ। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, 2026 के एशियाई खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है।

देश को भारतीय दल के
हर सदस्य पर गर्व है, जिन्होंने
समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ
भारत का प्रतिनिधित्व किया।
राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को
उनके खेल जीवन में निरंतर
सफलता और आगे भी कई
उपलब्धियाँ हासिल करने के
लिए शुभकामनाएँ दीं।

नयी दिह्नी ०४/१०
(संवाददाता): कांग्रेस ने
उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां द्वारा
मतदान के अधिकार को लेकर
दिये गये बयान का हवाला देते
हुए रविवार को दावा किया कि
उनकी टिप्पणियों से यह
साबित होता है कि मुख्य
निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ने
संविधान का धावना और उसके
प्रबंधनों का उल्लंघन किया है।
विवक्षी दल ने कहा कि
न्यायमूर्ति भुइयां की टिप्पणी ने
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश
कुमार को पूरी तरह बेनकाब
कर दिया है और अब उनके
पास पद पर बने रहने का कोई
नैतिक अधिकार नहीं रह गया
है। कांग्रेस महासचिव (संचार)
जयशंकर रमेश ने एक खबर साझा
की, जिसमें न्यायमूर्ति भुइयां के
हवाले से कहा गया है कि यदि
कि सी प्रक्रिया के

A portrait of a man with white hair and glasses, wearing a white shirt, speaking into a microphone. He is gesturing with his right hand. The background is a blurred image of a flag.

परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिक अपने ही देश में दोसम दर्जे के नागरिक बन जाएँ और उनके पास मतदान का अधिकार न रहे, तो ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह से मनमानी है। रमेश ने 'एक्स' पर कहा, "उच्चतम न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयाँ पर्यावरण संरक्षण के मुखर समर्थक रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने कहा, "अब इस सहस्रौ न्यायादिद ने जोरदार ढंग से साहसी मत व्यक्त किया है कि मतदान का अधिकार संविधान की मूल

सरचना का अभिन्न हिस्सा है।” उन्होंने कहा, “यह निर्णायक रूप से साबित करता है कि संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद सीईसी ने प्राधान्य का भ्रम और उसके स्वध्यान का उल्लंघन किया है।” रमेश ने कहा, “न्यायमूर्ति भुइयां ने इससे कहीं अधिक कहा है और उन्होंने सीईसी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। ज्ञानेश कुमार के पास अब पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।” कांग्रेस नेता का यह बयान समाचारपत्र ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद आया जिसमें कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी।

एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) ०४/१० (संवाददाता): अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एज्स), बिलासपुर का पहला दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा भी समारोह में शामिल होंगे। संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि दीक्षांत समारोह के मद्देनजर छह अक्टूबर (मंगलवार) को एज्स बिलासपुर में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) को सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। एज्स बिलासपुर में पहला शैक्षणिक सत्र 12 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ था। मंगलवार को ओपीडी में मरीजों का पंजीकरण और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध नहीं होगा। एज्स के रजिस्ट्रार राकेश कुमार सिंह ने मरीजों और आम लोगों से छह अक्टूबर को नियमित जांच या चिकित्सकीय परामर्श के लिए एज्स आने की योजना नहीं



बनाने का आग्रह किया है। मरीजों को किसी अस्वविधा से बचने के लिए नियमित स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए किसी अन्य दिन का समय लेने का सलाह दी गई है। हालांकि, ओपीडी बंद रहने के बावजूद एग्ज की आपातकालीन सेवाएँ सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

केंद्रीय मंत्री नड्डा के प्रस्तावित दौरों के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार, वह सोमवार को दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए बिलासपुर पहुंचेंगे और रात अणने पैतृक स्थान विजयपुर में रूकेंगे। प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने कहा कि नड्डा के शाम करीब छह बजे चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से खाना होने, रात करीब नौ बजे विजयपुर पहुंचने और मंगलवार को दीक्षा समारोह में शामिल होने की उम्मीद है।

मोहन चरण

भुवनेश्वर ०४/१०
(संवाददाता): ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर राज्य सरकार ने दो विरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों के निलंबन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निलंबित किए गए दोनों अधिकारियों अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं। सरकारी सेवा नियमों के तहत निर्धारित अवधि से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार विश्वाल और कटक सर्किल जेल के विरिष्ठ अधीक्षक सुजीत कुमार बाडी शामिल हैं। दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी अलग-अलग मामलों में हुई है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर उनके खिलाफ विभागीय प्रक्रिया शुरू

की गई और निलंबन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, अरुण कुमार विश्वाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। वह राज्य के वाणिज्य एवं परिवहन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। गिरफ्तारी के बाद उनके लगातार न्यायिक हिरासत में रहने को देखते हुए सरकारी सेवा नियमों के तहत कारावाड़ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसी तरह कटक सर्किल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक सुजीत कुमार राउल भी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। वरिष्ठ पद पर कार्यरत अधिकारी के जेल में रहने के बाद उनके निलंबन से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दोनों मामलों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के बाद निलंबन को मंजूरी दे दी। सरकारी सेवा नियमों के अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक जेल या न्यायिक हिरासत



में रहता है तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान है। इसी नियम के तहत अरुण कुमार बिश्वाल और सुजीत कुमार राउल को निलंबित करने का फैसला लिया गया है।

दोनों अधिकारियों के जेल में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के बाद संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को प्रशासनिक नियमों के पालन से जोड़कर देखा जा रहा है। किसी अधिकारी के गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने की स्थिति में उसके सरकारी पद पर बने रहने



को लेकर सेवा नियमों में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर संबंधित विभाग की ओर से निलंबन का प्रस्ताव तैयार किया गया और अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी मिलने के बाद दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन प्रभावी हो गया है।

अब निलंबन की अवधि के दौरान दोनों अधिकारी अपने संबंधित पदों पर कार्य नहीं कर सकेंगे। उनके मामलों में आगे की स्थिति न्यायिक और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर तय होगी। वाणिज्य एवं परिवहन विभाग में अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर

वरिष्ठ अधिकारी निलंबित

तेनात अरुण कुमार बिश्वाल के खिलाफ हुई कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं कटक सर्किल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक सुजीत कुमार राउल के निलंबन के बाद जेल प्रशासन में भी संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। सरकारी सेवा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए निर्धारित सेवा नियमों में गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत से संबंधित परिस्थितियों के लिए अलग-अलग प्रावधान मौजूद हैं। इनमें 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने की स्थिति में निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान भी शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान संबंधित अधिकारी अपने पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन न करें। मुख्यमंत्री कार्यालय की सूचना के मुताबिक दोनों अधिकारियों के मामले अलग-अलग हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में रहने के कारण निलंबन की कार्रवाई समान सेवा नियम के

तहत की गई है। राज्य सरकार ने दोनों मामलों में निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समाने रखा था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माथी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अब दोनों अधिकारी निलंबित रहेंगे। हालांकि निलंबन को अंतिम दंड के रूप में नहीं देखा जाता। संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और अन्य विभागीय कार्रवाई अपने स्तर पर जारी रह सकती है। आगे की कार्रवाई मामलों की स्थिति और सक्षम अधिकारियों के निर्णय के आधार पर होगी। इस कार्रवाई के साथ राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाकारियों के मामले में लागू सेवा नियमों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार विश्वाल और कटक सर्किल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक सुजीत कुमार राउल न्यायिक हिरासत में हैं और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद दोनों को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है।



विविध समाचार



अमित शाह जी, आप कहां हैं? जंतर-मंतर पर पुलिस २० साले पहले क्या हुआ था? ज्ञानेश कुमार की कथित बदसलूकी पर राहुल गांधी का सवाल से जुड़े मामले के पुराने रिकार्ड फिर तलब

नयी दिल्ली ०४/१० (संवाददाता): जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं और पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले पर जवाब मांगा है।

राहुल गांधी ने एज्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसलिए उन्होंने इस कथित बदसलूकी की जिम्मेदारी गृह मंत्री से लेने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक महिला पत्रकार ने जंतर-मंतर पर एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने लिखा,

उप्र चुनाव से पहले राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या कांग्रेस में होंगे शामिल?

नयी दिल्ली ०४/१० (संवाददाता): उजर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कांग्रेस में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य आज (शनिवार) को राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी अभी राष्ट्रीय स्तर पर स्थ, स्थ और पूरे देश से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं और इन मुद्दों के लिए सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं उजर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर काम कर रहा हूँ। हमारी विचारधारा और संघर्ष एक ही है... जहाँ हम उजर प्रदेश में इन अनेक समस्याओं से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है। इसीलिए आज

अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं बाबा, ज़्या कोई बुला सकता है?

लखनऊ ०४/१० (संवाददाता): उजर प्रदेश के इटावा में एक गैर-ब्राह्मण कथावाचक पर हमले को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धार्मिक नेता आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर कटाक्ष किया और कहा कि कई कथावाचक ऐसे हैं जो 50 लाख रुपये लेते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कई कथावाचक एक आयोजन के लिए 50 लाख रुपये लेते हैं। ज्या कोई धीरेंद्र शास्त्री को अपने घर पर कथा (धार्मिक समारोह) के लिए रख सकता है? वह कैसे गुप्त रूप से लेते हैं। यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर शास्त्री कहानी सुनाने के लिए कितना शुल्क लेते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह मुज्त नहीं है। शास्त्री की



सैकड़ों पत्रकार सिर्फ इस मांग को लेकर घंटों से बैठे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। ज्या यह पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य नहीं है? उन्होंने अब तक मामला तक दर्ज नहीं किया। जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि सबकुदर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज



गठबंधन के साथ जुड़ने का फैसला लिया गया। इस मामले पर बातचीत हुई; साथ ही, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनें। इसके लिए मैं समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ हूँ... आज मुलाकातों की बस शुरुआत हुई है; आगे ज्या होगा, इसकी जानकारी सही समय पर दी जाएगी। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बृहस्पति गठबंधन में शामिल होने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। यह चुनाव के नतीजे

ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है – इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं।

पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं – मगर जिस पुलिस

आने तक जारी रहेगी। उजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आराधना मिश्रा-मोना और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इमरान मसूद की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी व्यक्ति की जाति या धर्म ही एकमात्र पैमाना नहीं होता। अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति में कोई कमी थी; बल्कि इसका मतलब यह है कि वे कहीं और भूमिका निभाने वाले हैं।

पर महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है – वो आखिर किसकी हिफाजत कर रही है?

दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहां हैं आप? जवाब आपको ही देना है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शनिवार को जंतर-मंतर से सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कैमरे छीने गए, पत्रकारों को घसीटा गया और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाएं और छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर डर के बीच सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन जिन पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही पुलिस उन पर हाथ उठा रही है। राहुल गांधी ने सवाल किया,

ब्रिटिश दौर में भी सिविल सेवा परीक्षा में संस्कृत का पर्चा था-पीएम मोदी

नयी दिल्ली ०४/१० (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता से पहले की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े एक ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी सिविल सेवा परीक्षा में संस्कृत का एक प्रश्नपत्र होता था। राष्ट्रीय राजधानी के 'भारत मंडप' में बृहस्पतिवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई अभिलेखीय प्रदर्शनी के एक विवरण का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में अपनी परीक्षा के दौरान संस्कृत विषय की परीक्षा दी थी। मोदी ने कहा, "गैलरी को देखते हुए मैंने ध्यान दिया कि इसमें यह जानकारी भी दी गई है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए परीक्षा दी थी। उन्होंने कहा, "मेरा ध्यान इस बात ने खींचा कि उस समय भारत ब्रिटिश शासन होने के

जो सरकार एक महिला की शिकायत दर्ज करने से भी डरती है, वह आखिर किसकी रक्षा कर रही है?

राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे सवाल करते हुए लिखा, अमित शाह जी, आप कहां हैं? आपको इस बदसलूकी का जवाब देना ही होगा। छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए बयान जारी किया है। एआईएसए का आरोप है कि प्रदर्शन स्थल पर पुरुष पुलिस अधिकारियों ने महिला प्रदर्शनकारियों, वकीलों और पत्रकारों के साथ हाथापाई की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। संगठन ने कहा कि खुद को न्याय की रक्षक बताने वाली पुलिस भीड़ को संभालने के बुनियादी नियमों का भी पालन करने में नाकाम रही।



बावजूद परीक्षा में संस्कृत एक प्रश्नपत्र हुआ करता था, जिसे सुभाष बाबू ने भी दिया था।" प्रधानमंत्री ने बोस और अन्य ऐतिहासिक विभूतियों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले एक शताब्दी में कई लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया को विश्वास की विरासत में बदल दिया और इस संस्था को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मोदी ने युवा अर्थवर्धियों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से भारत की सिविल सेवा व्यवस्था की गहरी ऐतिहासिक यात्रा को समझने के लिए गैलरी देखने का आग्रह किया। यूपीएससी के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष स्मारक सिक्का, डाक टिकट और भारत में लोक सेवा आयोगों को आकार देने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को दर्ज करने वाली एक पुस्तक भी जारी की।

महाबोधि मंदिर का नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंप दें...सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नयी दिल्ली ०४/१० (संवाददाता): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के बोधगया में ऐतिहासिक महाबोधि महावीर मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने के लिए केंद्र और बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी।

पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका विचारणीय नहीं है।

हम यह कैसे करेंगे? यह अनुच्छेद 32 के तहत



बनाए रखने योग्य नहीं है। हम परमादेश कैसे जारी कर सकते हैं?

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कृपा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। हम इस पर विचार नहीं करते। खारिज। उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई, अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया। याचिका

नयी दिल्ली ०४/१० (संवाददाता): केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नित्थला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े करीब दो दशक पुराने मामले की विजिलेंस जांच को फिर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इसमें एक विदेशी इंजीनियर की आत्महत्या और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के गृह विभाग ने वर्ष 2006 में हुई विजिलेंस जांच से जुड़े रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव थे। यह जांच केएसटीपी के तहत एमसी रोड के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। यह मामला पीएटीआई-बेल नाम के इंडो-मलेशियन कंसोर्टियम से जुड़े इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या के बाद सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियर ने कथित तौर पर आत्महत्या से पहले लिखे नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम लिया था।

नोट में प्रोजेक्ट से जुड़े भुगतान और बिलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाने की



बात सामने आई थी। बताया गया कि प्रोजेक्ट के तहत भुगतान और बिलों के निपटारे को लेकर कथित तौर पर विवाद हुआ था। इसके बाद उस समय की एलडीएफ सरकार ने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। करीब दो दशक पुराने इस मामले को ऐसे समय में फिर चर्चा में लाया जा रहा है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।

हाल के दिनों में रमेश चेन्नित्थला ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि, पुरानी विजिलेंस जांच में ज्या निष्कर्ष निकला था और मौजूदा जांच



हूँ। मुझे वैसी ही हरी-भरी, साफ़-सुथरी, प्रगतिशील और सुरक्षित दिल्ली चाहिए जो मेरे बड़े होने के दिनों का एक अहम हिस्सा थी। भारतीय राजनीति में एक दशक से ज्यादा के अनुभव के बाद, मेरा सच में मानना ? है कि सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। अगर कोई एक नेता है जो सच्चा और ईमानदार है, तो वह राहुल गांधी हैं। वह मुश्किलों का सामना करने वाले और मजबूत

इरादों वाले नेता हैं। यह जरूरी है कि हम सब एक साथ आएँ। कक्कड़ ने कहा कि वह बीजेपी की पिछड़ी सोच वाली राजनीति को हराने के लिए पार्टी में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गर्व के साथ कांग्रेस में शामिल हो रही हूँ। अब हमें वोटों को बंटने नहीं देना है। हमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ना है और बीजेपी को पिछड़ी सोच वाली राजनीति को भी हराना है।

में रखते हुए सौंपा जाए।

महाबोधि मंदिर – एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक – 1949 अधिनियम के तहत प्रशासित है, जो बिहार सरकार की देखरेख में एक प्रबंधन समिति को नियंत्रण सौंपता है, जिसमें हिंदुओं और बौद्धों दोनों का

प्रतिनिधित्व होता है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान शासन संरचना बौद्धों के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करती है और मंदिर पर विशेष बौद्ध नियंत्रण की मांग करती है, जिसमें जोर दिया गया है कि यह स्थल वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है।

कलिंग समाचार

THE KALINGA SAMACHAR

(A Hindi Daily News Paper)

PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com



विविध समाचार



बच्चों के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं समय, अपनाएं ये 6 टिप्स



आज की बिजी लाइफस्टाइल में माता-पिता के पास इतना समय भी नहीं होता कि वह अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम रह पाएं, लेकिन आप चाहें तो कुछ बातों का खयाल रख अपने अपने बच्चों के सकारात्मक विकास में सहायक बन सकते हैं।

टिप्स: जिन फैमिली में खाना साथ होता है, वे साथ रहते हैं, सुनिश्चित कीजिए कि हमेशा खाना साथ अगर यह सम्भव ना हो तो कम से कम हरेक रात का खाना तो साथ जरूर खाएं। इससे आपको बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। खाने का समय परिवार के लिए जुड़ने का समय होता है। बातचीत हल्की और मजेदार रखिए। यह तरीके, मूल्य, स्वस्थ लाइफस्टाइल, कारिवायिक पाक विधियों और परंपरा आदि के बारे में बचाने के विचारों से भी अच्छा समय होता है।

टिप्स: बच्चों का स्कूल होमवर्क में उनकी हेल्प करें और टाइम गुजारें। इससे आपके उनकी पढ़ाई की गतिविधि से भी जुड़ी रहेंगे और बच्चों की आपकी बचाने में सहायता मिलेगी। पढ़ाई में स्कूल के प्रति उनकी सोच भी बेहतर होगी। इसके अलावा इससे उसका आत्मविश्वास और नैतिक बल बढ़ेगा।

टिप्स: आपके बच्चों को कौन से खेल सबसे ज्यादा पसंद हैं वह पता कीजिए। उसके साथ कीड़ियों गेम, बोर्ड गेम और पजल आदि खेलने का समय निश्चित कीजिए।

टिप्स: बच्चों के साथ निश्चित रूप से बिडिया पर संग्रहालय, पार्क, पुस्तकालय और दूसरी जगहें घूमने जाएं। बाहर निकलने की योजना बनाने में अपने बच्चों को भी शामिल कीजिए। बच्चों के अगर लगता है कि वे योजना बनाने के हिस्सा हैं तो वे खुद को महत्वपूर्ण भी समझते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि इसे सफल बनाएं।

टिप्स: साथ-साथ एक ऐसी परियोजना शुरू कीजिए जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकें। एक साथ काम कीजिए और एक ही साथ खर्च कीजिए। गुडिया का घर या पशु का घोंसला बनाने पर विचार कीजिए। परियोजना का चुनाव करते समय अपने बच्चों की दिलचस्पी, आयु ध्यान देने की क्षमता और कौशल का ध्यान जरूर रखिए।

टिप्स: सुनिश्चित कीजिए कि आप जो कम्प्लिटी टाइम प्लान करें, वह नियमित रूप से सम्पन्न हो। एक साप्ताहिक कैलेंडरी नाइट की योजना बनाइए। यह सप्ताह में एक बार शाम में पूरे परिवार के लिए अर्धपूर्ण महसूस करने जैसा कुछ हो सकता है।



घर परिवार



गर्भावस्था के दौरान न करें इन अजीबोगरीब बातों पर भरोसा



जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके पास हर तरफसे कई तरह की सलाहों की बाढ़ होने लगती है। जिनमें से कुछ सलाह और नुस्खे वाकई काम के होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अंधविश्वास और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होते हैं।

गर्भवती महिलाएं, ऐसे समय में शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजर रही होती हैं, ऐसे में एक अंदरूनी डर हमेशा बना रहता है और यही डर उन्हें इन भांतियों को मानने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में आपके थोड़ा समझदार बनने की जरूरत है।

ये सलाह बेहद आम है। गर्भवती महिला के सामने सुंदर से बच्चे की तस्वीर लगाने से होने वाला बच्चा भी कुबसूत पैदा होता है। दरअसल, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्भ में पलने वाले बच्चे के नैन-नकश जीवन पर निभर कर रहे हैं।

सालों से होने के बाद नारियल पानी पीने से बच्चे का दिमाग भी नारियल जितना बड़ा हो जाता है। लेकिन वो किसी भी तरह से मस्तिष्क के आकार के लिए जिम्मेदार नहीं होता है।

सुबह का पहला निक्काला सफेद खाना चाहिए,

इससे बच्चे का रंग खराब होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मिथ है। गर्भ में पलने वाले बच्चे का रंग-रूप जोन पर निर्भर करता है, ऐसे में आप चाहे सफेद खाएं या फिर काला बच्चों के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता है।

ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को छिप जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचना चाहिए।

ग्रहण एक निश्चित प्रक्रिया है और इसका बच्चे के जन्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। खलाँक, इसका मतलब ये निकलना नहीं है कि ग्रहण को बेपरवाह होकर नंगी आंखों से देखा जाए लेकिन, ये बात केवल गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लागू होती है।

गर्भ के आकार से बच्चे का लिंग पता चल जाता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प मिथ है। गर्भ का आकार, गर्भ में बच्चे की पोषीयता के बारे में बताता है।

स्वास्थ्य

अपने आप से कहें, आप सबसे सुंदर हैं

प्रत्येक महिला चाहे वह हाउसवाइफ हो या प्रोफेशनल सभी अपनी तुलना को लेकर हमेशा सतर्क रहती हैं और हमेशा आकर्षण का केंद्र बनना चाहती हैं। सबसे बढ़िया दिखने के लिए स्टाइल और खजान कम करने की उनकी कोशिश जब कारगर साबित नहीं होती तो इसका असर उनकी सोच, शक्तियुक्त, व्यवहार और उनके सामाजिक जीवन पर पड़ने लगता है। इसलिए अब समय है अपनी बाँधी इमेज को सुधारने का और अपना मनोबल बढ़ाने का।

अपने विचारों को काबू में रखें :-

आप सोचते हैं कि आपके मोटापे या शारीरिक ढांचे की वजह से आप आकर्षक नहीं रह जाएंगी, तो इस पर आप सोचना बंद कर दीजिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस बारे में ज्यादा सोचने का यह असर होगा कि आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, स्वीमिंग करना आदि से दूर हो जाएंगी।

एक ही धुन में मत रहिए:-

मतलब कि अपने आप को पाला-दुकला दिखाने के लिए एक ही धुन मत पकड़िए कि आपको फलना होना है।

पतले होने की चिंता में आप पतले होंगे या नहीं वह तो पता नहीं, परन्तु मानसिक तौर पर बीमार जरूर हो जाएंगे। अपना वर्कआउट प्लान करें, परन्तु तनाव से नहीं बल्कि पूरा मजा लेते हुए करें। साथ ही तब किए प्लान से एक भी ज्यादा चौकलेट न खाएं। एक ही आईना का उपयोग करें।

आत्मआलोचना से बचें (खुद की बुराई मत करें)

आप अपने नकारात्मक विचारों को बदलें और सिर्फ सकारात्मक लोगों के साथ रहें। यह कहने कि

बनाएं कि मुझे अपनी कमर से नफरत है यह कहिए कि मेरे होट लिफे सुंदर है। सुंदरा भीतर होती है और ज्यादातर स्वरूप और लंबा जीवन जीने के लिए होता है। समय-समय पर अपनी तारीफकरना ब 'धन्यवाद' कहना इसमें मददगार साबित होता है। ये आपको खामियों को नहीं बल्कि आपकी खुशियों को उजागर करता है।

बेहतरीन ड्रेसिंग :-

बेहतरीन ड्रेसिंग से आप अपने शरीर को खूबसूरत दिखा सकते हैं। उसी तरह के कपड़े, छिंट या रंगों का इस्तेमाल करें जिनसे आप का शरीर हल्का दिखेगा और आरामदायक रहे।

अपने शरीर से प्यार करना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और अपने उत्साह को बढ़ाना है ताकि आप कभी भी अपनी तुलना की वजह से अपने आप को छोटा न महसूस करें।

इन 5 से निकलवाना है काम तो करें कठोर व्यवहार

हमें वचन से ही सीखा जाता है कि सभी से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये बात सही भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ सदैव कठोर व्यवहार ही करना चाहिए अन्यथा वह ऐसा परिणाम नहीं देंगे जैसा हम चाहते हैं। यही बात गुरु पुराण भी लिखी है। गुरु पुराण में ऐसे 5 लोग ब चीवें बताई गई हैं, जिनके साथ कठोर अनुशासन जरूरी है अन्यथा वे हमारे मनमायिक परिणाम नहीं देंगे। यदि इनके साथ नरमी से बात करेंगे तो वे आपको बात कभी नहीं मानेंगे। ये 5 इस प्रकार हैं:-



1. दुर्जन यानी बुरे स्वभाव वाला

दुर्जन यानी बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ यदि आप नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में वह आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। उल्टा वह आपके मन स्वभाव का फायदा उठाने की कोशिश ही करेगा। इसलिए यदि आपको किसी दुर्जन व्यक्ति से काम निकलवाना हो तो उसके साथ कठोरता से ही बात करनी चाहिए, तभी वह आपके साथ अनुकूल व्यवहार करेगा।

2. शिल्पकार यानी कारीगर या मजदूर

गुरु पुराण में शिल्पकार से भी कठोर व्यवहार करने के लिए कहा गया है, जिससे अभिप्राय उन लोगों से है जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते और आलस्य करते हुए काम को टालते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि नम्रतापूर्ण बात की जाए तो वह ठीक से अपना काम नहीं करेंगे इसलिए यदि इन लोगों से अपना काम निकलवाना है तो इनके साथ कठोर व्यवहार करना बहुत आवश्यक है।



धर्म-संस्कृति



3. दास यानी नौकर

यदि आप नौकर से नम्रता पूर्ण व्यवहार करेंगे तो वह आपको किसी आज्ञा का पालन नहीं करेगा और आपके साथ मित्र के समान आचरण करने लगेगा। ऐसी स्थिति में वह आपको अपमान भी कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपने नौकर को कठोर अनुशासन में रखना अनिवार्य है। इसलिए यदि आपको दास यानी नौकर से काम करवाना है तो उसके साथ कठोर अनुशासन रखना बहुत आवश्यक है।

4. दोलक

दोलक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे यदि आप धीरे-धीरे घेम पूर्वक बजाने का प्रयास करेंगे तो उसकी आवाज वैसी नहीं आएगी, वैसी आप चाहते हैं यानी वह ठीक से काम नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि दोलक की आवाज जोर से आए तो आपको उसे अपने दोनों हाथों से जोर-जोर से पीटना होगा तभी दोलक से वैसी आवाज आएगी, वैसी आप चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि दोलक के साथ भी कठोर अनुशासन (जोर-जोर से पीटना) रखना चाहिए।



5. मनमानी करने वाली पत्नी

हिंदू धर्म में पत्नी को बहुत ही सम्माननीय माना गया है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में सीखना भी जरूरत है। पत्नी को अधीन भी कहा गया है जिसका अर्थ है शरीर का अंश भाग। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव मनमानी करने वाला है तो वह किसी के रूप में आपका नुकसान कर सकती है। मनमानी से अर्थ है ऐसी पत्नी को जो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तथा अन्य पुरुषों में भी आकर्षण रखती है। ऐसी स्त्री के साथ कठोर व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छंद होने पर वह अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।



कलिंग समाचार



संपादकीय

नेहरू और बाबरी मस्जिद

देश के पहले प्रधानमंत्री पं.नेहरू का खौफ समूची भाजपा पर इस कदर तारी है कि उसे नित नए झूठ अपने बचाव में गढ़ने पड़ते हैं। नेहरू की जीवनशैली, उनकी महिला मित्र, खान-पान की आदतों को लेकर संघ ने खूब झूठ फैलाया, फिर भाजपा ने इस काम को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया आने के बाद इस दुष्प्रचार में और तेजी आई, फिर भी नेहरू के नाम पर कोई दाग भाजपा नहीं लगा पाई। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, अपने नाम की माला जपवाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बसे जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिटा पाते। पुरानी पीढ़ी के नेताओं की बात छोड़ दें, नयी पीढ़ी के वैश्विक नेता भी नेहरू-गांधी को ही याद करते हैं। कोई सावरकर, गोलवलकर से प्रेरित होने की बात नहीं कहता। यही पीड़ा संघ को सालती है कि उनके प्रातस्मरणीय पुरुषों के नामलेवा दुनिया में क्यों नहीं हैं। यह डर और पीड़ा तो लाइलाज है, लिहाजा बेसिरपैर की बातों से भाजपा अपना मन बहलाने में लगी है। ऐसी ही एक बेतुकी बात का उदाहरण पेश किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान राजनाथ सिंह ने दावा किया कि, पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहते थे। यदि किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे। राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए बताया कि पटेल ने इसे सार्वजनिक दान से ही कराया, जिसमें 30 लाख रुपये जुटाए गए, लेकिन कोई सरकारी धन नहीं लगा। इसके बाद नेहरू-पटेल की परंपरा में जबरन नरेन्द्र मोदी को जोड़ने की कोशिश में राजनाथ सिंह ने कहा कि सोमनाथ की तरह, अयोध्या में मौजूदा राम मंदिर का निर्माण भी पूरी तरह जनता के योगदान से हो रहा है। सिंह ने नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें पटेल की विरासत को मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पुनर्स्थापित किया। राजनाथ सिंह का यह भाषण न केवल घोर हिंदा के योग्य है, बल्कि सिरे से झूठा होने के कारण गहन चिंताजनक भी है। जब देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोग झूठे बयान देने लगें तो सत्यमेव जयते के ध्येय वाक्य की रक्षा कैसे होगी। ऐतिहासिक दस्तावेज के मुताबिक बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कराया था। यह मस्जिद पहले से मौजूद थी और 1947 से 1964 तक नेहरू के कार्यकाल में इसके नए निर्माण का कोई प्रस्ताव या प्रमाण नहीं मिलता। सब जानते हैं कि पं. नेहरू सरकारी धन के दुरुपयोग के स त खिलाफ थे। वे खुद अपना खर्च भी बड़ी किफायत से चलाते थे और ऐसे कई प्रसंग हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका स्टाफ अक्सर उनसे उनके पैसे ही बचा कर रखता था, क्योंकि वे जरूरतमंदों को दे देते थे और खुद उनके पास फिर पैसे नहीं बचते थे। नेहरू हर तरह की धर्मांधता और सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वे धार्मिक आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के भी खिलाफ थे। बल्कि उनके हिसाब से औद्योगिक कारखाने ही आधुनिक भारत के तीर्थ हैं। अगर नेहरू के बाद की तमाम सरकारें इसी सिद्धांत पर चलती तो आज भारत विकास में चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को टक्कर देता। लेकिन धर्म के नाम पर राजनैतिक समझौता करने की नीति ने देश को पीछे ही रखा। नेहरू जैसी दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति उनके बाद के प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाए। नेहरू सरकार को धार्मिक कार्यों में संलग्न होने या जनता के धन को धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल करने के स त खिलाफ थे। इसलिए 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान नेहरू ने सरकारी फंडिंग का विरोध किया था, जिसे पटेल ने सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से पूरा कराया था। सरदार पटेल भी नेहरू जैसे ही सिद्धांतवादी थे। उन्होंने कहा था कि जब तक वह जिंदा हैं सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खज़ाने से एक पैसा नहीं देंगे। तो भारत के संविधान और नेहरू-पटेल की नीतियों में कोई भेद नहीं था। जबकि आज की सरकार इसके बिल्कुल उलट काम कर रही है।

जगदीश रत्तनानी

भारत में उत्पादकता कम है, इसलिए नहीं कि भारतीय श्रमिक कम उत्पादक हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें अधिक उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक निवेश अक्सर कमजोर या न के बराबर होते हैं। इसके अलावा बिजनेस चेन एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ काम करती है जो श्रम को खर्च करने के रूप में देखती है, जहां एक ढीली नियामक प्रणाली है और जहां श्रम कानून के उल्लंघन से बचना आसान है। लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि भारत के श्रम कानून-व्यापार, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को कार्यप्रवण होने और देश की विकास गाथा में शामिल होने से रोकते हैं। अब, भारत के 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) में समेकित कर 21 नवंबर को अधिसूचित किया गया है। इसे सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम कहा है जो परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत करता है और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल की नींव रखता है%। कई पर्यवेक्षकों ने इसे भारत में सुधारों की यात्रा में सबसे बड़े कदमों में से एक बताते हुए इसका स्वागत किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में श्रम कानून और वास्तव में कई अन्य कानून, प्रथाएं और परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं जिनमें से कई ब्रिटिश राज के जमाने से हैं और पुनरावलोकन के योग्य हैं। सामान्य तौर पर 29 कानूनों की आलोचना की जा रही है। इन कानूनों की समीक्षा एक

शकील अख्तर

अब बंगाल में 44 मुस्लिम विधायक हैं। और हुमायूँ कबीर बिहार के सीमांचल की तरह वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों से भी मुस्लिम को जिताने की अपील कर रहे हैं। नतीजा बिहार जैसा ही खतरनाक होगा। अपनी जो पार्टी बनाकर वे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें अगर मुसलमान बह गया तो वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। हुमायूँ कबीर की तो हो सकता है एक-दो सीटें आ जाएं। 33 साल में पहली बार उत्तर भारत में 6 दिसंबर को शांति रही। कहीं भी पराक्रम दिवस के उग्र प्रदर्शन या बाबरी मस्जिद शहादत का सार्वजनिक गम और गुस्सा प्रकट नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवा दिया। उसी के आर्डर के अनुरूप अयोध्या में जो मस्जिद बनना थी उसका अभी नींव का पत्थर भी नहीं रखा गया। लेकिन बंगाल में इस समय हिन्दू-मुस्लिम राजनीति की जरूरत है। वहां चुनाव हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से दो बार मोदी वहां कामयाब नहीं हो पाए हैं। विधानसभाओं में सबसे तीखा चुनाव उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही लड़ा। महिला मु यमंत्री पर व्यक्तिगत स्तर पर हमला किया। दीदी ओ दीदी इस तरह बोले कि उससे उपहास और अपमान साफ तौर पर प्रतिध्वनित हो रहा था। मगर जनता ने दीदी ओ दीदी को फिर जिता दिया था।

2016 और 2021 दोनों में नाकामयाब होने के बाद इस बार भाजपा अपने सबसे कामयाब हथियार मंदिर-मस्जिद को वहां लेकर आई है। 1992 के इस मंदिर-मस्जिद इशु ने ही उसके बाद

स्वागतयोग्य कदम होना चाहिए लेकिन इस तरह के विशाल परिवर्तन को कम से कम कुछ आम सहमति के साथ तैयार किया जाए ताकि यह सभी को साथ ले जा सके, विशेष रूप से ट्रेड यूनियंस को।

नई श्रम संहिताओं के सामने पहली बाधा यह है कि यह वास्तविक हितधारक ट्रेड यूनियन्स को सबसे अधिक प्रभावित करेगा और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। इससे ये बहु-प्रशंसित सुधार उन बदनाम कृषि कानूनों की श्रेणी में आ गए हैं जिन्हें इसी तरह पारित किया गया था और बाद में बड़े पैमाने पर अशांति के बाद वापस लिया गया था। वास्तव में कृषि कानूनों और अब अधिसूचित श्रम संहिताओं के बीच कुछ समानताएं हैं-दोनों को सितंबर, 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था, दोनों को जोरदार विरोध के बीच पारित किया गया था और दोनों को लाए जा रहे बदलाव के महत्व को न समझते हुए बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया था। उन दिनों सरकार को विश्वास था कि वह कठोर कदम उठाएगी जिससे कृषि कानून पारित हो गए लेकिन बाद में किसानों के जोरदार विरोध से हैरान रह गई और कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। दूसरी ओर, श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से उठे बस्ते में स्थानांतरित कर दिया गया जिसे अब पुनर्जीवित किया गया है। श्रमिक संघ कमजोर हैं इसलिए श्रमिक आंदोलन इतनी आसानी से शुरू नहीं हो सकते हैं; पर

बंगाल में

हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाया था और भाजपा का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। 1996 में हुए चुनाव में कांग्रेस हारी और अदल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि रहे कुछ ही दिन मगर बीजेपी का हमेशा का एक सपना पूरा हो गया और आगे का रास्ता खुल गया।

अब बंगाल में इसी मंदिर-मस्जिद इशु को जोर-शोर से चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हुमायूँ कबीर को भाजपा के पुराने नेता हैं उसके टिकट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं उनके जरिए बंगाल के मुर्शीदाबाद में एक मस्जिद की नींव का पत्थर रखवाया गया और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। ठीक उसी नकशे को वहां प्रदर्शित किया गया जैसी गिराए जाने से पहले अयोध्या में मस्जिद थी। यहां यह बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर जो मस्जिद बनना है स्थानीय मुसलमानों ने उसका नाम भी बाबरी मस्जिद नहीं रखा है। मगर वहां से सैंकड़ों किलोमीटर दूर मुर्शीदाबाद बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद उसी स्थापत्य की बनाने की शुरुआत की गई है।

बीजेपी नेताओं के उग्र बयान आप देख रहे होंगे। टीवी की आग लगाऊ डिबेटें भी। यही उद्देश्य था। मुसलमानों को फिर टारगेट पर लिया जाना और हिन्दुओं का धुवीकरण। धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए एक नया चैलेंज। टालने से काम नहीं चलेगा। सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा। बंगाल की जनता धर्मनिरपेक्ष है। मगर

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नया प्रयास नकारात्मक नोट पर खुलता है।

कोई भी यह तर्क नहीं दे रहा है कि श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने चाहिए जैसा कि कृषि कानूनों के मामले में तर्क दिया गया

कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभावी होने के बाद ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों ने अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और वे अपनी सुरक्षा के लिए मीलों पैदल चल कर कंगाल, बदहाल, भूखे-प्यासे अपने गांव पहुंचे थे। ज्यादा जानें उत्पादकता प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश समाचार क्षेत्रीय समाचार खेल जगत अपडेट संपादकीय लेख संग्रह राजनीतिक विश्लेषण सेवा युवा समाचार पत्र टैबलेट कविता संग्रह बहरहाल, जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया.

था। भारतीय संदर्भ में समस्या कानूनी संहिताओं के बारे में नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने की स्थिति के बारे में है और जो सत्ता के गलियारों, मालिकों और निदेशकों के बोर्ड रूम से स्पष्ट रूप से विपरीत हैं। बाजार की यह वास्तविकता जब एक ऐसी सरकार से मिलती है जिसने श्रमिकों के साथ पूंजी का निर्माण नहीं किया है और जिसे व्यापार लॉबी के पक्ष में काम करने के रूप में देखा जाता है, तो वास्तव में विश्वास गायब हो जाता है। सरकार ने खुद को और तथाकथित सुधारों को उन उपायों के माध्यम से आगे बढ़ाकर नुकसान पहुंचाया है जो भयंकर प्रतिरोध को ट्रिगर

करेंगे।

श्रम कानूनों की दिशा कार्यबल को औपचारिक बनाने की ओर है जबकि औपचारिक क्षेत्र में भी कई कमियां हैं। जिस बात का दावा किया जाता है और जिसका वास्तव में अनुभव किया जाता है, उसके बीच

करने वाले नेता जब उनके आपूर्तिकर्ता कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं।

इनमें कई कार निर्माता नेता हैं। इसे रोकने के लिए कानून में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं लेकिन उन्होंने इस पर अमल क्यों नहीं किया? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नए कानून कैसे और क्यों काम करेंगे? खासकर उन परिस्थितियों में जब कानूनों को उद्योग के अधिक अनुकूल बनाने और जुमाने के लिए जगह बनाने तथा अपराधों के गैर अपराधीकरण करने की दिशा में है? ध्यान दें कि 22 सितंबर, 2020 को लोकसभा ने चार श्रम संहिताओं में से तीन को पहली बार पारित किया था, उसी दिन सरकार ने सदन में बताया था कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मार्च, 2020 में पैदल यात्रा करने वाले लोगों सहित 1.06 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने गृह-राज्य लौट आए। कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभावी होने के बाद ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों ने अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और वे अपनी सुरक्षा के लिए मीलों पैदल चल कर कंगाल, बदहाल, भूखे-प्यासे अपने गांव पहुंचे थे। ज्यादा जानें उत्पादकता प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश समाचार क्षेत्रीय समाचार खेल जगत अपडेट संपादकीय लेख संग्रह राजनीतिक विश्लेषण सेवा युवा समाचार पत्र टैबलेट कविता संग्रह बहरहाल, जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया तो जो दूसरा सबसे शर्मनाक कृ त्य था कि उद्योग संघों ने श्रम मंत्री से

मुलाकात की और श्रम कानूनों की सुरक्षा को हटाने के लिए कहा ताकि व्यवसाय फिर से शुरू हो सके! यह सब हाल ही का इतिहास है। उस समय व्यवसायों के साथ सांटाण्ट कर श्रम संहिताओं का जन्म हुआ था। यह देखते हुए कि भारतीय श्रमिक कम शिक्षित, कम जागरूक, कम कुशल, कम समर्थित और इतने कम उत्पादक हैं और अक्सर नौकरी, किसी भी नौकरी के लिए बेताब होते हैं, यदि हम कार्य प्रणाली पर विचार करें तो देख सकते हैं कि समस्या की जड़ में श्रम शक्ति के प्रति एक निश्चित अवहेलना है जो वैसे भी शोषणकारी प्रथाओं के लिए प्रवृत्त है। भारत में उत्पादकता कम है, इसलिए नहीं कि भारतीय श्रमिक कम उत्पादक हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें अधिक उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक निवेश अक्सर कमजोर या न के बराबर होते हैं। इसके अलावा बिजनेस चेन एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ काम करती है जो श्रम को खर्च करने के रूप में देखती है, जहां एक ढीली नियामक प्रणाली है और जहां श्रम कानून के उल्लंघन से बचना आसान है। भारतीय व्यापार क्षेत्र जब श्रम को एक संपत्ति के रूप में देखना और मानना ​​शुरू कर देंगे, उनके विकास और कल्याण में निवेश करेंगे तो अगले आर्बिट में चले जाएंगे एवं श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को लाल रेखाओं को पार करने के लिए महंगा भुगतान करना होगा। हो सकता है कि नई श्रम संहिताएं हमें वहां तक न ले जाएं।

हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी

सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। उसे सांप्रदायिकता के जाल में जाने से बचाना होगा। ज्यादा जानें बाबरी मस्जिद क्षेत्रीय समाचार अलर्ट स पादकीय सामग्री मनोरंजन समाचार क्षेत्रीय समाचार कविता संग्रह संपादकीय लेख संग्रह समाचार पत्र सदस्यता ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट विशेष रिपोर्ट सदस्यता रोजमर्रा की ज़िन्दगी से जुड़े मुद्दों को उठाना होगा। मगर सबसे पहले यह सोचना होगा कि इस सांप्रदायिक मामले को कैसे डि यूज करना है। यह दोनों तरफ आग लगाएगा। और जहां हिन्दू-मुसलमान का धुवीकरण हुआ बीजेपी को रास्ता मिल जाएगा। और बीजेपी अगर बंगाल के जीत गए तो फिर विपक्ष के लिए कोई विधानसभा सेफ नहीं बचेगी। सोचना मुसलमानों को भी होगा। उनके धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के नेता जिस तरह जज्बाती सवाल उठा रहे हैं उसके पीछे की मंशा समझना होगी। अभी हुमायूं कबीर से पहले ओवैसी इसी तरह एक नान इशु मुस्लिम कयादत (मुसलमानों का नेता मुसलमान) उठा चुके हैं। परिणाम बिहार में उन्हें तो पांच सीटें मिल गईं मगर मुस्लिम विधायकों की सं या पिछली बार के 19 से घट कर 11 रह गई। जब स्थिति सामान्य रहती है हिन्दू-मुसलमान नहीं होता तो मुस्लिम विधायक भी उचित सं या में चुने जाते हैं। 1985 में जब ओवैसी और भाजपा दोनों की सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी तो वहां 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल में ओवैसी की जज्बाती तकरीरों

में फंसकर मुसलमानों ने उनके 5 विधायक तो जीता दिए मगर बाकी बिहार में केवल 6 ही मुस्लिम विधायक जीत पाए। अब बंगाल में 44 मुस्लिम विधायक हैं। और हुमायूं कबीर बिहार के सीमांचल की तरह वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों से भी मुस्लिम को जिताने की अपील कर रहे हैं। नतीजा बिहार जैसा ही खतरनाक होगा। अपनी जो पार्टी बनाकर वे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें अगर मुसलमान बह गया तो वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। हुमायूं कबीर की तो हो सकता है एक-दो सीटें आ जाएं मगर उसकी कीमत पर भाजपा की सीटें कितनी आएंगी सोच लीजिए। सरकार भी बना सकती है और फिर बुलडोजर से लेकर क्या-क्या आएगा इसे मुसलमानों को सोचना है।

बीजेपी और संघ परिवार तो सामने से उसके खिलाफ है। मगर इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा होता नहीं। उसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब हिन्दुओं में प्रतिक्रिया हो। आज 11 साल के मोदी शासन के बाद भी देश का अधिकांश बहुसं यक उसके साथ नहीं है। 37 प्रतिशत के आसपास ही उसका वोट शेयर डगमगा रहा है। इसलिए खुद सांप्रदायिक इशु उठाने के साथ उसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इशु उठाने वाले चाहिए। राजनीति में ओवैसी के बाद उसे हुमायूं कबीर मिल गए। और धार्मिक नेताओं में देश के सबसे बड़ी मौलानाओं के संगठन जमीयत उल उलेमा के मदनी परिवार का साथ। पहले दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम भी

बहुत साथ देते थे। मगर इन दिनों कुछ खामोश हैं। अच्छी बात है। लेकिन मदनी परिवार जिसके पास देवबंद जैसा सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केन्द्र है अपनी आपसी लड़ाई में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए फिजूल के इशु उठा रहा है। झगड़ा चाचा-भतीजे का है। कई सालों से संपत्ति और संस्थानों पर कब्जे का। संपत्ति अथाह है। देश विदेश सब जगह फैली हुई और संस्थान हैं जमीयत, देवबंद जैसे प्रतिष्ठित। ऐतिहासिक मस्जिदें। पहले चाचा अरशद मदनी ने एक बिलकुल अप्रासंगिक बात की। मुसलमान के किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने की। यहां सेना की मुस्लिम कर्नल पर सवाल उठ रहे हैं। वहां व्यक्तिगत पदों को जिक्र करके सिवाय फितूर फैलाने के और क्या मिलेगा? इतना पैसा, संसाधन हैं कुछ अपने शिक्षा केन्द्र खोलते। मगर कुछ नहीं। दिल्ली में पांच माइनरटी कालेज हैं। क्रिश्चियन और सिखों के। मुस्लिम का एक भी नहीं। जाकिर हुसैन कालेज का नाम मत लेना। वह मुस्लिम मैनेजमेंट के द्वारा संचालित नहीं है। सरकारी कालेज है। माइनरटी कालेज का मतलब होता है उसके द्वारा संचालित और उसके समुदाय के बच्चों को एडमिशन में विशेष छूट। इसी तरह क्रिश्चियन मशीनरी और सिखों के दिल्ली में कई अच्छे स्कूल हैं। जहां सभी समुदायों के लोग एडमिशन के लिए मारा-मारी करते हैं। मुसलमान भी। लेकिन खुद मुसलमानों का एक भी नहीं। खैर चाचा के बाद भतीजे महमूद मदनी ने और भी



विविध समाचार



5100 नवजन्मी बेटियों की लोहड़ी : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सशक्त संदेश : डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़ / जालंधर : बेटी बचाओदृष्टी पढ़ाओ के उद्देश्य को और सुदृढ़ करते हुए गांव घुड़का के जोहल फार्म में 5100 नवजन्मी बेटियों के सम्मान में लोहड़ी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर, पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल, तथा पंजाब एग्री फूड कॉरपोरेशन

लिमिटेड के चेयरमैन मंगल सिंह बस्सी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने बेटी बचाओदृष्टी पढ़ाओ के संदेश को समाज तक और अधिक मजबूती से पहुंचाया। इस अवसर पर पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए कहा कि 5100 नवजन्मी बेटियों की लोहड़ी मनाना समाज में बेटियों के प्रति बदलती

सकारात्मक सोच का स्पष्ट प्रतीक है। उन्होंने नवजन्मी बेटियों के माता-पिता को लोहड़ी पर्व की बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना बदलती सामाजिक सोच की वास्तविक पहचान है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बच्चियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण

सुनिश्चित करने के लिए कई जनहितकारी योजनाएं लागू कर रही है, ताकि हर बेटी को सम्मान, समानता और आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं और गांव स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी ही बेटी बचाओ अभियान को सफल बना सकती है। इस प्रकार के सामूहिक आयोजन नई पीढ़ी

में समानता, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस पहल के लिए जोहल फार्म सेवा सोसायटी और कार्यक्रम से जुड़े अन्य सहयोगियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक प्रयास बेटियों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



चंडीगढ़। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी से जुड़े सरपंच जरमल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले को लेकर सोमवार को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी साझा की। डीजीपी के अनुसार, सरपंच हत्याकांड में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 2 की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के रायपुर से, 2 मोहाली से और 3 तरनतारन से की गई है। डीजीपी ने बताया कि रायपुर से पकड़े गए सुखराज सिंह निवासी तरनतारन और कर्मजीत सिंह निवासी गुरदासपुर ने ही सरपंच पर गोलियां चलाई थीं। इसके अलावा जोबनजीत सिंह समेत दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है वहीं आज सुबह पुलिस ने कुलविंदर सिंह किंवा, अरमानदीप सिंह और हरदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि रायपुर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को वहां की स्थानीय अदालत में

पेश कर 14 दिन के ट्राजिट रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद उन्हें हवाई मार्ग से पंजाब लाया जा रहा है। डीजीपी ने यह भी खुलासा किया कि इस हत्या की साजिश विदेश में बैठे एक हैंडलर ने रची थी। सरपंच जरमल सिंह की गैंगस्टर प्रभ दासुवाल के साथ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। डीजीपी गौरव यादव ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि कोई पंजाब में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो पंजाब पुलिस उसे देश या विदेश कहीं भी छोड़ेगी नहीं। उल्लेखनीय है कि तरनतारन क्षेत्र के रहने वाले सरपंच जरमल सिंह की 4 जनवरी को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अमृतसर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वारदात के बाद दोनों शूटर छत्तीसगढ़ फरार हो गए थे और रायपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां छिपे हुए थे। रविवार को रायपुर और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

पंजाब में सीएम चेहरा नहीं बनाएगी कांग्रेस, इंचार्ज बघेल बोले सबसे बड़ा चेहरा होगा सिर्फ राहुल गांधी

बठिंडा। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में सीएम फंस बनने की रेस शुरू होने से पहले ही रुक गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस का कोई भी सीएम चेहरा नहीं होगा। बठिंडा पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में चेहरा सिर्फ राहुल गांधी का ही होगा। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सब चेहरा हैं लेकिन सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। उसके पहले सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। अभी भी हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल, विध

ानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता खुद को सीएम फंस समझने लगे थे। लेकिन कांग्रेस इंचार्ज के इस बयान के बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं को झटका लगा है। हालांकि राजा वड्डिंग और रंधावा पहले ही सीएम चेहरे का दावा छोड़ चुके हैं। बघेल का सीधे तौर पर कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित न करने की बात कहना 2022 के चुनाव से सबक लेना है। तब चन्नी और नवजोत सिद्ध की लड़ाई से कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई। इस बार हाईकमान नहीं चाहता कि सीएम कुर्सी को लेकर झगड़ा शुरू हो। पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इन दिनों बिना किसी विवाद या खुली बयानबाजी के मुख्यमंत्री चेहरे की अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हैं। वर्ष 2021 में कैप्टन

अमरिंदर सिंह को पद से हटाए जाने के बाद चन्नी को प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। हालांकि उन्हें मात्र तीन महीने का कार्यकाल मिला, लेकिन उस दौरान लिए गए उनके फंसले कांग्रेस को लगातार सुर्खियों में ले आए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा हालात में

पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस ही मुख्य मुकामले में नजर आती है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने तरनतारन उपचुनाव और जिला परिषददृष्टिकोण समिति चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन फिलहाल वह कांग्रेस के बराबर की स्थिति में नहीं दिखता। भाजपा की बात करें

तो उसका वोट शेयर भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसकी पकड़ अभी कमजोर बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के लिए पंजाब एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि यह उन राज्यों में शामिल है जहां भाजपा की राजनीतिक मौजूदगी सीमित है।

पंजाब सीएम सेहत बीमा योजना की लॉन्चिंग टली, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कारण

चंडीगढ़। पंजाब सरकार की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, जो पहले 15 जनवरी को लॉन्च होनी थी, जो अब 22 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। योजना के लॉन्च में यह एक सप्ताह की देरी जल्थेदार साहिब द्वारा

मुख्यमंत्री को समन किए जाने के कारण हुई है। यह जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने फतेहगढ़ साहिब में दी। वह यहां योजना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना

के औपचारिक शुभारंभ से पहले इसका ट्रायल रन किया जाएगा, ताकि किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक खामी को दूर किया जा सके। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया

है। योजना का लक्ष्य करीब 3 करोड़ लोगों को कवर करना है। सरकार की कोशिश है कि हर पात्र नागरिक को सेहत बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आधार कार्ड पंजाब का होना चाहिए

है। योजना का लक्ष्य करीब 3 करोड़ लोगों को कवर करना है। सरकार की कोशिश है कि हर पात्र नागरिक को सेहत बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आधार कार्ड पंजाब का होना चाहिए

और वोटर कार्ड पंजाब का होना चाहिए। जो बच्चे हैं, उनका डिपेंडेंट कार्ड होना चाहिए। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हमें कई अन्य सोर्स से भी पैसे आने हैं। सरकार 1200 से 1500 करोड़ खर्च करेगी तो इससे लोगों का फायदा

होगा। इससे लोगों को इमरजेंसी केयर मिलेगी। सेहत मंत्री ने कहा कि यह योजना बहुत अच्छी है। जैसे फ्री बिजली की योजना दिल्ली में केंजरीवाल सरकार ने शुरू की। इसे आगे पंजाब में सीएम भगवंत मान ने बढ़ाया।

आतिशी के फर्जी वीडियो में गुरुओं का नाम जोड़ कर भाजपा ने की बेअदबी : भगवंत सिंह मान

बठिंडा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के दिल्ली विधानसभा के वीडियो से छेड़छाड़ करने के लिए भाजपा की कड़ी निंदा की और इसे पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की नीच साजिश करार दिया। धर्मनिरपेक्ष पंजाब सरकार ऐसे मंसूबों को सफल नहीं होने देगी, यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो को एडिट करके इसमें जानबूझकर गलत शब्दावली शामिल की गई है, जो सिख धर्म की घोर बेअदबी है। साथ ही उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि आतिशी ने अपने बयान में कहीं भी "गुरु" शब्द नहीं बोला। भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह झूठी वीडियो क्लिप विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं नहीं है और भाजपा चंडीगढ़, बीबीएमबी तथा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर पंजाब विरोधी मानसिकता से चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्षी दलों के नेता नीच राजनीति करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा न होने के कारण इस झूठ का बचाव करने के लिए बेचौन हो रहे हैं। बठिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शुरू से ही भाजपा ने फिफ्टीपरसेंटी, बंटवारा और नफरत की राजनीति की है और इसी के हिस्से के रूप में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के मद्देनजर भाजपा ने पंजाब में लोगों को सांप्रदायिक लकीरों पर बांटने के लिए इस एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया है।

भाजपा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ करके इसमें आपत्तिजनक शब्दावली शामिल की है। यहां तक कि फॉरेंसिक जांच में भी स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि 'आप' नेता ने कहीं 'गुरु' शब्द बोला ही नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना भगवा पार्टी की पुरानी रणनीति है और इस कार्रवाई ने सिख संगत की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है क्योंकि वीडियो से छेड़छाड़ करके उन्होंने सिखों की बेअदबी की है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नीच हरकत करने वालों को उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ के बारे में पूरी स्पष्टता हो गई है क्योंकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सदन की कार्यवाही में यह शब्द कहीं भी बोले नहीं दिखाई देते। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिस नेता ने सोशल मीडिया पर यह एडिटेड (छेड़छाड़ वाला) वीडियो अपलोड किया था, उसे अपने कुकर्मा के नतीजे भुगतने पड़ेंगे और पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ सही केस दर्ज किया है। यहां दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है। कपिल मिश्रा पर आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़, बीबीएमबी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गणतंत्र दिवस की झांकियों और अन्य मामलों पर भाजपा के पंजाब विरोधी रुख के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के प्रति भगवा पार्टी का रवैया हमेशा दुश्मनी वाला

रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज एक अजीबोगरीब स्थिति में घिर गए हैं क्योंकि वे बार-बार झूठ का सहारा लेकर पंजाब के प्रति भाजपा के रवैये को जायज ठहराने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और उसकी लीडरशिप में महान सिख गुरु साहिबान के प्रति सम्मान की भावना कहीं नजर नहीं आती और प्रधानमंत्री को तो कभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस (शहीदी वर्षगांठ) की याद में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता स्वीकार करने का समय भी नहीं था। हर कोई जानता है कि न तो प्रधानमंत्री और न ही भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता या केंद्रीय मंत्री इन कार्यक्रमों में नतमस्तक होने के लिए पंजाब आया। यह सिखों और हमारे महान गुरु साहिबान के प्रति एक तंग और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पंजाब और इसकी सरकार के खिलाफ एक ही पटरी पर चल रहे हैं। ये पार्टियां एक ही दिन अलग-अलग समय पर एक जैसे प्रेस नोट भी जारी करती हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य राज्य सरकार के खिलाफ जहर फैलाना है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर बादल पंजाब के मुद्दों पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये वही नेता हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए सहमति दी थी और जिन्होंने काले कृषि कानूनों के लिए मोदी की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां पहले नशा तस्करों

और गैंगस्टरों को संरक्षण भी देती रहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भी वे गैंगस्टरों को टिकटें दे रहे हैं। पूर्व कांग्रेसी मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर वार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि रंधावा को याद रखना चाहिए कि उनके पिता ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए बधाई दी थी। गुरदासपुर से वर्तमान लोकसभा सदस्य उसी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसने सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा न होने के कारण विपक्षी दलों के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सबके बावजूद भी मेरी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और सर्वपक्षीय विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में प्राप्ति्यों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस स्कूलों में अपग्रेड किया जा रहा है और राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण में पहली बार केरल को पछाड़ते हुए देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा, 265 ने जेईई और 45 ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंसिपलों और शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर, फिनलैंड और अहमदाबाद भेजा जा रहा है।



कक्षा एक से आठ तक की नई पाठ्य पुस्तकों में मिलीं १७४१ गलतियां, १० अधिकारियों पर कार्रवाई

भुवनेश्वर ०४/१० (संवाददाता): ओडिशा में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई नई पाठ्यपुस्तकों में बड़ी संख्या में गलतियां सामने आई हैं। राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि नई पाठ्यपुस्तकों में कुल 1,741 गलतियां पाई गई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के पूर्व निदेशक और तीन पूर्व उप-निदेशक भी शामिल हैं, जिन्हें सेवा से निलंबित किया गया है। मंत्री नित्यानंद गोंड ने विधानसभा में विधायक गौतम बुद्ध दास के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई नई पाठ्यपुस्तकों की जांच में अलग-अलग स्तर पर कुल 1,741 त्रुटियां सामने आईं। इतनी बड़ी संख्या में गलतियां सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की गई। इसके आधार

पर कुल 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्री के मुताबिक स्पष्टचक्र के एक पूर्व निदेशक और तीन पूर्व उप-निदेशकों को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा छह उप-निदेशकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इस तरह पाठ्यपुस्तकों में मिली त्रुटियों के मामले में कुल 10 अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि पाठ्यपुस्तकों की तैयारी और उनसे जुड़ी प्रक्रिया में सामने आई खामियों को गंभीरता से लिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों के विद्यार्थियों की प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार होती हैं। छोटे बच्चों के लिए किताबों में दी गई जानकारी ही विभिन्न विषयों की बुनियादी समझ विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में पाठ्यपुस्तकों में बड़ी संख्या में गलतियां मिलना शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर विषय माना जा रहा है। पाठ्यपुस्तकों की सामग्री तैयार



करने से लेकर उसकी समीक्षा और अंतिम प्रकाशन तक कई स्तरों पर जांच की प्रक्रिया होती है। इसके बावजूद 1,741 गलतियां सामने आने के बाद इस पूरी प्रक्रिया की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी। इससे साफ है कि सरकार ने केवल त्रुटियों की पहचान तक मामला सीमित नहीं रखा, बल्कि जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। SCERT शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और शैक्षणिक सामग्री की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता



है। ऐसे में इसके पूर्व निदेशक और पूर्व उप-निदेशकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई मामले को गंभीरता को दर्शाती है। सरकार के अनुसार चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिनमें एक पूर्व निदेशक और तीन पूर्व उप-निदेशक शामिल हैं। वहीं छह अन्य उप-निदेशकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार हालांकि विधानसभा में दी गई जानकारी में प्रत्येक गलती की अलग-अलग प्रकृति का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि 1,741 त्रुटियों में कितनी भाषाई, तथ्यात्मक, मुद्रण संबंधी या अन्य प्रकार की

जिम्मेदारी संबंधित जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी। नई पाठ्यपुस्तकों में सामने आई त्रुटियां भविष्य में किताबों की तैयारी और समीक्षा की प्रक्रिया में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता को भी रेखांकित करती हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री तैयार करते समय विषय विशेषज्ञों, भाषा विशेषज्ञों और संपादकीय टीम के स्तर पर प्रभावी जांच महत्वपूर्ण होती है।

खासकर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किताबों में भाषा और तथ्यों की शुद्धता जरूरी है। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बच्चे पुस्तकों में लिखी सामग्री को प्रमाणिक मानकर सीखते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती उनके सीखने की प्रक्रिया पर असर डाल सकती है। विधानसभा में मामला उठने के बाद सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में यह साफ हुआ कि गलतियों की पहचान की जा चुकी है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सरकार कुल 10 अधिकारियों के खिलाफ कदम

उठाए गए हैं। इनमें चार अधिकारियों का निलंबन और छह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है। यह कार्रवाई पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में उठाया गया कदम है। फिलहाल सरकार के सामने पाठ्यपुस्तकों में मिली गलतियों को सुधारने के साथ यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी है कि आगे विद्यार्थियों तक पहुंचने वाली शैक्षणिक सामग्री त्रुटिरहित हो। इसके लिए संपादन, समीक्षा और अंतिम सत्यापन की व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक होगा। ओडिशा विधानसभा में मंत्री नित्यानंद गोंड की ओर से दी गई जानकारी के बाद कक्षा 1 से 8 तक की नई पाठ्यपुस्तकों में मिली 1,741 गलतियों का मामला सामने आया है। सरकार ने मामले में 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब विभागीय कार्रवाई और भविष्य में पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर नजर रहेगी।

आरएसपी के एच.एस.एम.-2 में ए.आई.-आधारित सुरक्षा निगरानी प्रणाली स्थापित

राउरकेला ०४/१० (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) ने हॉट स्ट्रिप मिल-2 (एच.एस.एम.-2) में ए.आई.-आधारित डिजिटल सुरक्षा निगरानी परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह पहल प्रौद्योगिकी-सक्षम और सक्रिय कार्यस्थल सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर.एस.पी. की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम द्वारा एच.एस.एम.-2 और सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग (एस.ई.डी.) के सहयोग से इन-हाउस प्रयासों के माध्यम से विकसित एवं कार्यान्वित इस प्रणाली में निरंतर निगरानी के लिए 10



आई.पी. कैमरों का उपयोग किया गया है। इसका ए.आई.-आधारित कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हेलमेट संबंधी उल्लंघनों का पता लगाता है, स्वचालित अलार्म सक्रिय करता है, स्नेपशॉट कैप्चर करता है तथा समय-चिह्नित घटनाओं का

रिकॉर्ड रखता है। डेटा को केंद्रीय रूप से संग्रहित किया जाता है, जिससे सुरक्षा निगरानी, अनुपालन के आकलन और सूचित निर्णय लेने के लिए एक विश्वसनीय आधार उपलब्ध होता है। यह पहल आर.एस.पी. की आंतरिक टीमों की उस

क्षमता को प्रदर्शित करती है, जिसके माध्यम से वे परिचालन संबंधी सुरक्षा आवश्यकता की पहचान कर इस्पात संयंत्र के जटिल कार्य वातावरण के अनुरूप प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित कर सकते हैं।

डिजिटलाइजेशन टीम, एच.एस.एम.-2 और एस.ई.डी. के बीच घनिष्ठ समन्वय ने इस्पात संयंत्र के संचालन एवं सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञता को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा केंद्रीयकृत डेटा विश्लेषण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाया है। वर्तमान हेलमेट-डिटेक्शन एप्लीकेशन इस परियोजना का प्रथम चरण है। निरंतर विकास और ए.आई. मॉडल के क्रमिक प्रशिक्षण के साथ इस प्रणाली का विस्तार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.) से संबंधित अन्य उल्लंघनों, असुरक्षित कार्यों, असुरक्षित परिस्थितियों, आग तथा अन्य संभावित खतरों की

पहचान के लिए किया जा सकता है। इसमें आगे चलकर एक व्यापक ए.आई.-आधारित सुरक्षा प्रबंधन एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में विकसित होने की भी क्षमता है। सुरक्षा उल्लंघनों की स्वचालित पहचान और दस्तावेजीकरण के माध्यम से यह प्रणाली पी.पी.ई. अनुपालन को सुदृढ़ करने, पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने और समय पर हस्तक्षेप में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुरक्षा प्रबंधन में प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर पूर्वानुमानात्मक एवं निवारक कार्यप्रणालियों की ओर संक्रमण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यह परियोजना डिजिटल परिवर्तन, स्वदेशी नवाचार तथा अधिक सुरक्षित परिचालन और 'शून्य क्षति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आर.एस.पी. की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती है।

भुवनेश्वर ०४/१० (संवाददाता): एजसाइज डिपार्टमेंट द्वारा देर रात चलाए गए एक एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान भुवनेश्वर में 155 बार, पब, क्लब और बीयर पार्लरों पर छापा मारा गया, इस दौरान चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक बार में कथित तौर पर एक एजसाइज अधिकारी पर हमला किया गया। इस घटना के बाद, पुलिस ने हमले के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार रात को यह छापे इस इनपुट के बाद मारे गए कि कई प्रतिष्ठान तय समय से ज्यादा देर तक चल रहे थे और लाइसेंसिंग और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। चंद्रशेखरपुर इलाके के एक बार में इंस्पेक्शन के दौरान, लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर छापे का विरोध किया और अधिकारी के यूनिफॉर्म में होने के बावजूद एजसाइज कर्मियों



पर हमला किया। बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ने और मारपीट में बदलने से पहले इंस्पेक्शन में बाधा डाली गई।

इसके बाद चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पुष्टि की है कि घटना के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर चेकिंग रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोऑर्डिनेटेड टीमों ने भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर चेकिंग

की, जिसमें कुल 155 प्रतिष्ठानों को कवर किया गया। इंस्पेक्शन में ऑपरेटिंग घंटों, लाइसेंस की शर्तों और एजसाइज नियमों के तहत अन्य अनिवार्य प्रावधानों के पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। कई आउटलेट देर रात तक चलते पाए गए और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। हाल की आग की घटना के बाद चेकिंग में तेज़ी सुबह भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके के एक बार में आग लगने की बड़ी घटना के बाद हाल की सुरक्षा चिंताओं के बाद चेकिंग में तेज़ी लाई गई है।

जगतसिंहपुर में लापरवाही से खुदाई के कारण गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई



जगतसिंहपुर ०४/१० (संवाददाता): जगतसिंहपुर शहर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क से गैस लीक होने की कई घटनाओं ने निवासियों में डर और गुस्सा पैदा कर दिया है।

नागरिक और सरकारी एजेंसियों के लिए काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा लापरवाही से की गई खुदाई को ऐसी रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं का कारण बताया जा रहा है। शुक्रवार को, वार्ड नंबर 6 के ओहल गांव में सड़क निर्माण में लगे मजदूरों ने कथित तौर

पर एक गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया और घटना की रिपोर्ट किए बिना उसे मिट्टी से ढक दिया। जब एक शादी के जुलूस के दौरान पटराखे फोड़ने से लीक हुई गैस में आग लग गई, तो दहशत फैल गई। झत गैस रिसोर्सिंग लिमिटेड (झत्तक्र) के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और लीकेज को ठीक किया।

एक और घटना में, बिजली का खंभा लगाते समय एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये लीकेज झत्तक्र जगतसिंहपुर

नगर पालिका और अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण, नाली के काम, टयूबवेल लगाने और बिजली के खंभे लगाने के दौरान हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि झत्तक्र ने उपभोक्ताओं के साथ-साथ गृहस्थ स्टेशनों को गैस सप्लाई करने के लिए पारादीप से जगतसिंहपुर तक अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाई है। काम पूरा होने के साथ, 7,000 के लक्ष्य के मुकाबले नगर पालिका सीमा के तहत लगभग 1,200 घरों को कनेक्शन दिए गए हैं।

आरएसपी में दो मॉडल शिफ्ट कार्यालयों 'कर्मधारा' का किया गया उद्घाटन

राउरकेला ०४/१० (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में फंटलाइन कार्यबल समर्थन को मजबूत करने और एक सुरक्षित, अधिक उत्पादक और कर्मचारी-केंद्रित कार्यस्थल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, 'कर्मधारा' नाम के दो अत्याधुनिक मॉडल शिफ्ट कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा ने कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री विश्व रंजन पलाई, मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों की उपस्थिति में कार्यालयों का उद्घाटन किया। विशेष रूप से, दो शिफ्ट कार्यालय ज्लास्ट फर्नेस विभाग के उत्पादन नियंत्रण कक्ष में स्थित हैं और दूसरा स्टील मेल्टिंग शॉप-२ (एसएमएस-२) विभाग के



सीसीएम मैकेनिकल विंग में स्थित हैं। शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों और फंटलाइन टीमों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से निदेशक प्रभारी, आरएसपी के मार्गदर्शन में मॉडल शिफ्ट कार्यालयों की अवधारणा बनाई गई है। यह पहल इस सिद्धांत को पुष्ट करती है कि निरंतर उत्पादन उत्कृष्टता तब प्राप्त की जाती है

जब सुरक्षा गैर-परक्राज्य रहती है। मॉडल शिफ्ट कार्यालयों का नाम 'कर्मधारा' रखा गया है, जो काम, जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है जो आरएसपी के संचालन को बनाए रखता है। उन्हें सुरक्षा, उत्पादकता, कर्मचारी कल्याण और परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित किया

गया है। शिफ्ट टीमों के लिए समर्पित स्थानों के रूप में डिज़ाइन किया गया, कार्यालय फंटलाइन कर्मचारियों को प्रत्येक शिफ्ट के दौरान अपनी जिम्मेदारियों की योजना बनाने, समन्वय करने और प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए एक सुरक्षित, संगठित और अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। मॉडल शिफ्ट कार्यालयों की एक

प्रमुख विशेषता उनका आईटी-सक्षम बुनियादी ढांचा है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस है। यह फंटलाइन कर्मचारियों को सीधे शॉप फ्लोर से परिचालन और अन्य ऑनलाइन सिस्टम तक पहुंचने में सक्षम करेगा, सूचना तक समय पर पहुंच, निर्बाध संचार, आईजीओटी जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ई-लर्निंग और डिजिटल गतिविधियों के कुशल समापन की सुविधा प्रदान करेगा। दो मॉडल शिफ्ट कार्यालयों का विकास एक सहयोगी प्रयास रहा है जिसमें ज्लास्ट फर्नेस, एसएमएस-२, मानव संसाधन, सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं, एसी विभाग और सी एंड आईटी विभाग शामिल हैं, जिनकी सामूहिक विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता ने पहल के सफल समापन में योगदान दिया।